संक्षेप में

भारत को एपीआई उत्पादन बढ़ाने की जरूरत: यूनीकेम

दवा कंपनी यूनीकेम लैबोरेटरीज ने देश में आयात पर निर्भरता (खासतौर से चीन के आयात) कम करने के लिए, कच्चे माल का स्थानीय उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया है। दवा कंपनी ने 2019-20 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में शेयरधारकों से कहा कि मौजदा कोरोनावायरस महामारी ने यह बात साफ कर दी है कि देश में सक्रिय फार्मास्युटिकल अवयवों (एपीआई) के लिए क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। यूनीकेम लैबोरेटरीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रकाश मोदी ने कहा, हमारा देश अपने अधिकांश एपीआई के लिए चीन पर बहुत अधिक निर्भर है। आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत सरकार को एपीआई के निर्माण को बढ़ावा देने और एक स्वस्थ तथा आर्थिक रूप से मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र की जरूरत है। उन्होंने एपीआई के लिए अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देने की बात भी कही। *भाषा*

रिलायंस बनेगी एक नई ऊर्जा कंपनी

अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने खुद को एक नई ऊर्जा में तब्दील करने के लिए 15 साल की योजना बनाई है, जिसका मकसद कार्बन डाईऑक्साड को पुनर्चक्रित करना और प्लास्टिक कचरे का मूल्यवर्धन करना और स्वच्छ तथा वाजिब कीमत वाले ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देना है। बोफा सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक तेल से रसायन कारोबार करने वाली बड़ी कंपनियां हाल के दिनों में उपभोक्ता कारोबार पर खास ध्यान दे रही हैं, लेकिन रिलायंस का तेल से रसायन (ओटूसी) कारोबार लगातार मुक्त नकदी प्रवाह पैदा करने में सफल रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है, जब तक मांग सामान्य नहीं हो जाती, आरआईएल कच्चे माल के प्रसंस्करण का प्रवाह अधिकतम करने की कोशिश कर रही है, पेट्रोरसायन एकीकरण का लाभ उठाते हुए लागत पर ध्यान दे रही है और घरेलू ईंधन विपणन पर खास जोर दे रही है। *भाषा*

ओएनजीसी ने अपना कर्ज 35 फीसदी घटाया

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी ने अपने ऋण में करीब 35 फीसदी की कटौती की है। ओएनजीसी के अधिकारियों का कहना है कि इसके बावजूद तेल एवं गैस के दाम काफी नीचे आने की वजह से कंपनी के लिए योजनागत व्यय को पूरा करना एक चुनौती है। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि 31 मार्च, 2019 तक उसपर बकाया कुल कर्ज 21,593 करोड़ रुपये था। यह 31 मार्च, 2020 को घटकर 13,949 करोड़ रुपये रह गया है। कंपनी का कहना है कि बेहतर परिचालन से प्राप्त आय का इस्तेमाल उसने अपने कर्ज के बोझ को कम करने के लिए किया है। *भाषा*

नए रक्षा मानक मददगार साबित होंगे

सरकार के ऐलान के बाद स्थानीय कंपनियों के लिए 52,000 करोड़ रुपये के अवसर मौजूद हैं

बीएस संवाददाता
मुंबई, 9 अगस्त

- सरकार को स्थानीय कंपनियों को कॉस्ट-प्लस आधार पर दीर्घावधि अनुबंध देने की जरूरत
- भारतीय उद्योग अब अपने पूंजीगत खर्च और उत्पादन की योजना बना सकता है
- जरूरत हुई तो इन कंपनियों को अमेरिका की तरह सीएजी ऑडिट के दायरे में लाया जा सकता है जिससे कि ये कंपनियां मुनाफाखोर न बन सकें

रक्षा क्षेत्र में दिसंबर से 101 उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित उपाय स्थानीय कंपनियों के लिए मददगार साबित हो सकते हैं और इससे उन्हें स्थानीय निर्माण आधार खड़ा करने में मदद मिल सकती है।

रक्षा कंपनियों के मुख्य कार्याधिकारियों का कहना है कि यदि इस योजना पर सही तरीके से काम किया गया तो इससे भारत को इन रक्षा संबंधित उत्पादों का शुद्ध आयातक बनने के बजाय शुद्ध निर्यातक बनने में मदद मिलेगी। एक रक्षा कंपनी के मुख्य कार्याधिकारी ने नाम नहीं बताने के अनुरोध के साथ कहा, 'यह मेक इन इंडिया विजन कोसाकार करने की दिशा में एक अच्छा कदम होगा। इस तरह से अमेरिका सैन्य हार्डवेयर के निर्माण में विश्व दिग्गज बना। यह ऐसा निजी क्षेत्र है जो अमेरिका में आधुनिक प्लेटफॉर्म और उपकरण की आपूर्ति करता है और पूरी दुनिया इनके उत्पादों को हासिल करना चाहती है।'

सरकार को स्थानीय कंपनियों को कोस्ट-प्लस आधार पर दीर्घावधि अनुबंध देने की जरूरत है और यदि जरूरत हुई तो इन कंपनियों को अमेरिका की तरह सीएजी ऑडिट के दायरे में लाया जा सकेगा, जिससे कि ये कंपनियां मुनाफाखोर न बन सकें। उन्होंने कहा, 'भारत कुछ भी तैयार कर सकता है और निजी क्षेत्र दीर्घावधि अनुबंधों का आश्वासन मिलने पर देश में उत्पादन के लिए वैश्विक बाजार से निवेश और भागीदार ला सकता है। भारत को ऐसे अनुबंधों के लिए भरोसेमंद कंपनियों का चयन करने की जरूरत होगी।'

लार्सन ऐंड टुब्रो (एलऐंडटी) के अधिकारियों का कहना है कि सरकार ने अब आत्मनिर्भर मिशन पर सक्रियता बढ़ानी शुरू की है। एलऐंडटी में पूर्णकालिक निदेशक और वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष (रक्षा एवं स्मार्ट टेक्नोलॉजीज) जयंत पाटिल ने कहा, 'इस घोषणा ने भारतीय उद्योग को तैयारी के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा और दिशा प्रदान की है।'

अन्य मुख्य कार्याधिकारियों का कहना है कि घरेलू पूंजीगत खरीद के लिए 52,000 करोड़ रुपये निर्धारित करने की घोषणा रक्षा खरीद योजनाओं पर दीर्घावधि संभावना मुहैया कराने की भारतीय कंपनियों के पुराने सुझावों को पूरा करती है। फिक्की डिफेंस कमेटी के अध्यक्ष और एयरोस्पेस ऐंड डिफेंस के समूह अध्यक्ष तथा महिंद्रा ग्रुप के कार्यकारी बोर्ड सदस्य एसपी शुक्ला ने कहा, 'भारतीय उद्योग अब अपने पूंजीगत खर्च और उत्पादन की योजना बना सकता है।'

एलऐंडटी के पाटिल का यह भी मानना है कि सरकार भविष्य में संभावित ऑर्डर की वैल्यू की समीक्षा करेगी। उन्होंने कहा, 'आज की घोषणा में सरकार ने अगले 6-7 वर्षों के दौरान भारतीय उद्योग के लिए 4 लाख करोड़ रुपये मूल्य के ऑर्डर जारी किए जाने की प्रतिबद्धता जताई है। भारतीय रक्षा उद्योग के मौजूदा आकार को देखते हुए मुझे विश्वास है कि इसकी समीक्षा की जाएगी और इसे बढ़ाकर कुछ दिन पहले जारी रक्षा उत्पादन एवं निर्यात संवर्द्धन नीति में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप किया जाएगा।'

फिक्की की अध्यक्ष संगीता रेड्डी ने कहा कि नए नीतिगत उपाय भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी और उत्पादों में 'आत्मनिर्भर' बनाने में मददगार साबित होंगे। रेड्डी ने कहा, 'उद्योग आयात प्रतिबंध की इस सूची में कई और उत्पाद शामिल किए जाने की संभावना देख रहा है जिससे कि भारतीय उद्योग की क्षमताओं का इस्तेमाल कर स्वदेशीकरण की प्रक्रिया को मजबूत बनाया जा सके।'

देसी दवाओं की बिक्री ने जुलाई में किया निराश

सोहिनी दास
मुंबई, 9 अगस्त

देसी दवा बाजार ने जुलाई में महज 0.2 फीसदी की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की, जबकि जून में इस बाजार में सुधार के संकेत नजर आए थे। थेरेपी के ज्यादातर क्षेत्रों की बिक्री की रफ्तार में गिरावट दर्ज हुई। कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के बाद से बाजार की रफ्तार पर दबाव रहा है और दवाई के नए पर्चे कम रह गए। मई में भारतीय दवा बाजार में 9 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई जबकि अप्रैल में इस बाजार में 11 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई थी। जून में हालांकि कुछ सुधार नजर आया और बढ़त की रफ्तार 2.4 फीसदी के सकारात्मक दायरे में रही।

जून में सुधार के संकेत के बाद जुलाई में बढ़त रही मामूली

मार्केट रिसर्च फर्म एआईओसीडी अवैक्स के आंकड़ों के मुताबिक, कोविड संकट ने देसी बाजार की बढ़त की रफ्तार पर असर डाला है, हालांकि कुछ थेरेपी में जुलाई के दौरान सकारात्मक रफ्तार जारी रही।

क्रॉनिक थेरेपी की रफ्तार सकारात्मक बनी रही। उदाहरण के लिए हृदय रोग के इलाज वाले क्षेत्र में 13.1 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई जबकि मधुमेह रोधी क्षेत्र 5.9 फीसदी की रफ्तार से बढ़ा। श्वसन संबंधी रोग के इलाज वाली दवा के क्षेत्र की रफ्तार हालांकि घटकर -2 फीसदी रह गई। लॉकडाउन में ढील के बाद संक्रमणरोधी दवाओं की बिक्री जुलाई में 10.2 फीसदी घटी। संक्रमणरोधी (खास तौर से एंटीबायोटिक्स) दवाओं की बिक्री मॉनसून के दौरान सामान्यत: बढ़ती है क्योंकि जुकाम व बुखार आदि ज्यादा देखने को मिलती है।

विटामिन की बिक्री में सुधार आया और जुलाई में उसमें 5.5 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई क्योंकि ओटीसी इम्युनिटी बुस्टिंग दवाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कई कंपनियों ने या तो नई दवाएं पेश की या ऐसे ब्रांडों पर दोबारा ध्यान केंद्रित किया। उदाहरण के लिए डॉ. रेड्डीज लैब ने न्यूट्रास्युटिकल ब्रांड उतारा जबकि जुवेंटस हेल्थकेयर की जिंक सप्लिमेंट जिंकोनिया के प्रति बाजार में रुझान रहा।

जून की रफ्तार की आंशिक वजह पिछले साल का निचला आधार रही।

चौथी तिमाही में बाजार में उतरेगा केनरा बैंक

अभिजित लेले
मुंबई, 9 अगस्त

सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक की योजना मौजूदा वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 5,000 करोड़ रुपये की इक्विटी के साथ पूंजी बाजार में उतरने की है। इसके अलावा वह दूसरी तिमाही में 1,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त टियर-1 पूंजी जुटाएगा और उतनी ही रकम वित्त वर्ष 21 की तीसरी तिमाही में भी जुटाएगा। बैंक अपने कारोबार में इजाफे और महामारी के कारण लगे झटके को सहने के लिए पूंजी जुटा रहा है।

केनरा बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी एल वी प्रभाकर ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, फंडामेंटल के लिहाज से बैंक मजबूत है और बाजार से पूंजी जुटाने को प्राथमिकता देगा। बैंक ने सरकार से पूंजी नहीं मांगी है लेकिन वह सरकार से मिलने वाले इक्विटी समर्थन के लिए तैयार रहेगा। बैंक पहले ही इक्विटी व एटी-1 बॉन्ड के जरिए पूंजी जुटाने की तैयारी शुरू कर चुका है। 1 अप्रैल 2020 को सिंडिकेट बैंक के साथ उसका विलय हुआ और जून, 2020 के आखिर में उसका लोनबुक 6.5 लाख करोड़ रुपये और पूंजी पर्याप्त अनुपात 12.77 फीसदी है। इसके अलावा कॉमन इक्विटी टियर-1, 8.15 फीसदी रहा। विलय के बाद बनी नई इकाई का पूंजी पर्याप्तता अनुपात नए वित्त वर्ष की शुरुआत में 12.96 फीसदी था जबकि सीईटी-1, 8.40 फीसदी।

'संकट के बावजूद दिखी दमदार बुकिंग'

गोदरेज प्रॉपर्टीज ने वित्त वर्ष 2021 की जून तिमाही में 14.69 करोड़ रुपये का कर पूर्व घाटा दर्ज किया जबकि वित्त वर्ष 2020 की पहली तिमाही में उसने 140 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ दर्ज किया था। हालांकि वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही के दौरान कंपनी के नकदी प्रवाह और ग्राहकों से नकदी संग्रह में कमी आई लेकिन कंपनी के चेयरमैन **पिरोजशा गोदरेज** ने **राघवेंद्र कामत** से बातचीत में कहा कि निर्माण क्षेत्र में सुधार होने के कारण कारोबारी स्थितियां सुधर रही हैं। पेश हैं मुख्य अंश:

आपका ग्राहकों से नकदी संग्रह कोविड पूर्व स्तर के मुकाबले घटकर करीब 40 फीसदी रह गया है। चालू तिमाही के दौरान इसकी क्या स्थिति है?
अब स्थिति काफी बेहतर है। नकदी संग्रह का संबंध निर्माण चरणों तक पहुंचने से होता है और पहली तिमाही में शायद ही कोई निर्माण कार्य हुआ क्योंकि पूरा अप्रैल और अधिकांश मई लॉकडाउन में गुजर गया। हमारे श्रमिकों की संख्या अब कोविड पूर्व स्तर के मुकाबले 60 फीसदी तक पहुंच चुकी है। इसलिए हमारा मानना है कि आने वाली तिमाहियों में निर्माण और संग्रह दोनों सुधार होगा।

आपका शुद्ध ऋण भी बढ़कर 590 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि आने वाली तिमाहियों के दौरान इसमें और तेजी आएगी?
ऋण में भी उन्हीं कारणों से वृद्धि हुई है जिनका जिक्र मैंने पहले किया है। हमने नई परियोजनाएं शुरू की हैं और चौथी तिमाही के लिए कारोबार विकास एवं निर्माण संबंधी भुगतान करने थे। आगामी तिमाहियों में भी हमारे ऋण स्तर में वृद्धि जारी रहेगी क्योंकि हमारे पास बड़ी तादाद में नई परियोजनाएं लॉन्च होने के लिए तैयार हैं। पिछले साल के मुकाबले परिचालन नकदी प्रवाह कमजोर है लेकिन आगे चलकर उसमें सुधार होगा। हमें विश्वास है कि इस साल हम जो निवेश करने जा रहे हैं उससे आगामी वर्षों में दमदार नकदी प्रवाह का सृजन होगा क्योंकि हमारी नई परियोजनाएं शुरू हो रही हैं।

आपकी 10:90 की भुगतान योजना से बिक्री और बुकिंग को मदद मिली है लेकिन नकदी प्रवाह को झटका लगा है? क्या आप उसे जारी रखेंगे?
अब हरेक परियोजना की अपनी अलग भुगतान योजना है जो परियोजना रणनीति एवं रकम की जरूरतों से संबंधित है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2021 में 1.5 करोड़ वर्ग फुट की परियोजना लॉन्च करने की योजना बनाई थी। क्या आप उसे आगे बढ़ाएंगे?
नियामकीय मंजूरियां समय पर मिल जाए तो हम अपनी सभी योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। यदि बाजार के माहौल को देखते हुए जरूरत पड़ी तो निश्चित तौर पर हमें अपनी रणनीति में बदलाव भी करना पड़ेगा।

क्या आप अपनी परियोजनाओं के लॉन्च, मूल्य निर्धारण, अपार्टमेंट के आकार आदि में वर्तमान परिदृश्य के मद्देनजर बदलाव करेंगे?
हम अपनी परियोजनाओं की विशेषताओं और ग्राहकों की जरूरतों को लगातार मूल्यांकन करते रहते हैं लेकिन फिलहाल अपार्टमेंट के आकार अथवा मूल्य में बदलाव की कोई योजना नहीं है।

रिहायशी रियल एस्टेट में कब तक व्यापक सुधार होने की उम्मीद है?
इसका आकलन करना कठिन है लेकिन हमारा मानना है कि अगले कैलेंडर वर्ष से सुधार की शुरुआत हो सकती है। यह इस क्षेत्र के बाहर के तमाम कारकों पर निर्भर करता है जैसे कोविड वैश्विक महामारी की स्थिति, अर्थव्यवस्था एवं रियल एस्टेट क्षे। को रफ्तार देने के लिनए सरकार की पहल आदि। इस प्रकार धीरे-धीरे मांग में भी सुधार दिखेगा।

सुधार को लेकर आप किस प्रकार आश्वस्त हैं?
संकट के दौर में 2001 से ही किफायत बेहतरीन तरीका रहा है क्योंकि ब्याज दरें भी बिल्कुल निचले स्तर पर हैं। मौजूदा वैश्विक महामारी के दौर में जो लोग खुद के घर की सुरक्षा तले आना चाहते हैं वे मकान खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। कोविड संकट के बावजूद मार्च से ही हमें दमदार बुकिंग दिख रही है। इसलिए हमारा मानना है कि आगामी तिमाहियों में स्थितियां लगातार सुधरेंगी।

यूको बैंक UCO BANK
सम्मान आपके विश्वास का (भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय - II, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 3 और 4, डी डी ब्लॉक, सेक्टर -I, साल्ट लेक, कोलकाता - 700064

निविदा की सूचना

यूको बैंक निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) आमंत्रित करता है:-
1. कैपेक्स मॉडल पर 300 एटीएम की आपूर्ति, स्थापना और रखरखाव हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी)।
2. फिनेकल 10.X पर अंतिम उपयोगकर्त्ता प्रशिक्षण के लिए एमपीएलएस नेटवर्क कनेक्टिविटी की खरीद के लिए सेवा प्रदाता के चयन हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी)।
3. 30 एप्पल आइपैड (Apple iPad) की आपूर्ति हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी)।
किसी भी विवरण के लिए कृपया https://www.ucobank.com वेबसाइट देखें।

दिनांक :10.08.2020 उप महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बीपीआर एवं बीटीडी)

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

कॉर्पोरेट कार्यालय
254-260 अव्वै षण्मुगम सालै
रायपेत्त, *चेन्नै 600 014*

नोटिस

सेबी (लिस्टिंग की प्रतिबद्धताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के संदर्भ में एतत् द्वारा नोटिस दी जाती है कि बैंक के निदेशक मंडल की बैठक, अन्य बातों के साथ-साथ 30 जून 2020 को समाप्त तिमाही के लिए बैंक के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के अनुमोदन के लिए 14 अगस्त 2020 को आयोजित किया जाना निर्धारित किया गया है

विवरण के लिए बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in *और / या स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट* www.nseindia.com, www.bseindia.com *पर लॉग ऑन करें।*

स्थान : चेन्नै *दीनानाथ कुमार*
दिनांक : 07 अगस्त 2020 *सहायक महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
भोपाल संस्करण

बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटिड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा नई दुनिया न्यूज़ ऐंड नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, 23/4-23/5, गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर-डी, सीपेट हॉस्टल के पास, भोपाल, म.प्र. 462011 से मुद्रित एवं मानव निकेत, प्रथम तल, प्लॉट नं. 30, इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स, एम पी नगर, ज़ोन-1, भोपाल, म.प्र. 462011 से प्रकाशित
संपादक: कैलाश नौटियाल

आरएनआई न० WBHIN/2008/24333
पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं।
टेलीफोन - 033-22101314/1022/1600 फैक्स- 033-22101599
सबस्क्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए कृपया संपर्क करें..
सुश्री मानसी सिंह
हेड कस्टमर रिलेशन्स
बिज़नेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, तीसरी और चौथी मंजिल, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, सेंचुरी मिल्स के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई 400 013
ई मेल.. subs_bs@bsmail.in
या 57007 पर एसएमएस करें SUB BS

डिसक्लेमर.. बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉर्पोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से परे परिस्थितियों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिज़नेस स्टैंडर्ड कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के सभी विज्ञापन सद्भाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिज़नेस स्टैंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए। मैं० बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा० लि० का सर्वाधिकार सुरक्षित है। बिजनेस स्टैंडर्ड प्रा० लि० से लिखित अनुमति लिए बगैर समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस तरह का निषिद्ध एवं अनधिकृत कार्य करने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरु की जाएगी।

कोई हवाई अधिभार नहीं

श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
SHRIRAM HOUSING FINANCE

पंजीकृत कार्यालय : कार्यालय सं. 123, अंगप्पा नैकेन स्ट्रीट, चेन्नई-600 001 **मुख्य कार्यालय** : लेवल 3, वोखार्ट टॉवर्स, ईस्ट विंग, सी-2 ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुम्बई 400 051, दूरभाष : 022 4241 0400, 022 4060 3100 **वेबसाइट** : http://www.shriramhousing.in, **शाखा कार्यालय** : प्लॉट सं. 7, द्वितीय तल, क्वालिटी बिजिनेस सेंटर, एमपी नगर, जोन II, भोपाल-462011

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) का प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार/रों एवं जमानती/यों को सूचना दी जाती है कि द श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया गया है, की बिक्री तालिका में वर्णित के अनुसार कर्जदारों एवं जमानतियों से द श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बकायों की वसूली के लिए ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर ई-नीलामी के माध्यम से 14.09.2020 को 12.00 बजे अप. से 2.00 बजे अप. के बीच की जायेगी। कर्जदारों तथा जमानतियों के विवरण, बकाया राशि, अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण तथा उस पर ज्ञात ऋणभार, आरक्षित मूल्य एवं जमा धरोहर राशि तथा वृद्धि भी निम्नवत दी गयी है :

कर्जदारों/सहकर्जदारों/ जमानतियों/ बंधककर्ताओं के नाम	13(2) माँग सूचना की तिथि एवं राशि	सम्पत्ति का विवरण	ज्ञात ऋण भार	आरक्षित मूल्य (रु.)	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (रु.) एवं संविदा वृद्धि	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) का विवरण	नीलामी की तिथि एवं समय	सम्पर्क व्यक्ति तथा निरीक्षण की तिथि
श्री अजय वर्मा पुत्र बाबूलाल वर्मा एवं श्रीमती नीतू वर्मा पत्नी अजय वर्मा **ऋण खाता सं.** SHLHBHOP0000357	6.11.2019 को रु. 38,06,002/- (रुपये रुपये अड़तीस लाख छः हजार दो मात्र) तथा भावी ब्याज एवं लागत प्रभार **माँग सूचना की तिथि** 07.11.2019 **कब्जा करने की तिथि एवं कब्जे का प्रकार** 10.02.2020 **भौतिक कब्जा**	फ्रीहोल्ड आवासीय प्लॉट, खसरा नं. 128 का भाग, भारती नगर, सेकदा खोड़ी रोड, ग्राम शेरपुर, जिला सिहोर (म.प्र.) में स्थित। माप 2900 वर्ग फीट सीमाएँ : पूर्व : यादव की भूमि पश्चिम : 20 फीट रास्ता उत्तर : विक्रेता की भूमि दक्षिण : सुनील वर्मा का प्लॉट	नहीं	रु. 28,20,000/- (रुपये अट्ठाईस लाख बीस हजार मात्र)	रु. 2,82,000/- (रुपये दो लाख बयासी हजार मात्र) **संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि** 11.09.2020 **समय : 10.00 बजे पूर्वा. से 05.00 बजे अप. तक** **संविदा वृद्धि** **रु. 20,000/- एवं इसके गुणक में**	ईएमडी आरटीजी/ एनईएफटी के माध्यम से नीचे वर्णित खाते में जमा की जानी है : **बैंक का नाम** : एक्सिस बैंक लिमिटेड **शाखा** : बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, मुम्बई **बैंक खाता नं.** : चालू खाता नं. 911020013220315 **आईएफएससी कोड** : UTIB0000230	**14 सितम्बर, 2020** **समय : 12.00 बजे पूर्वा. से 02.00 बजे अप. तक**	**रघुवीर सिंह चौहान** +8120000486 **सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि :** 10-09-2020 **को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. तक**

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की वेबसाइट http://shriramhousing.in/e-auction-Residential.php देखें।

स्थान : सिहोर **ह./- अधिकृत प्राधिकारी**
तिथि : 10.08.2020 **श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

मझोली आईटी कंपनियों को क्लाउड, लागत घटाने से दम

साई ईश्वर
मुंबई, 9 अगस्त

मझोले आकार की आईटी सेवा कंपनियां लागत नियंत्रण संबंधी उपायों और क्लाउड एवं मोबिलिटी में ग्राहकों से बढ़ती मांग के बल पर कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रभाव को कम करने में सफल रही हैं। जून में समाप्त तिमाही के दौरान इन कंपनियों राजस्व एवं मुनाफे के मोर्चे पर देश की शीर्ष पांच आईटी सेवा कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया।

कैपिटालाइन से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, नौ मिडकैप आईटी सेवा कंपनियों के राजस्व में सालाना आधार पर औसतन 8.9 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई जबकि शीर्ष पांच आईटी सेवा कंपनियों के राजस्व में औसतन महज 4 फीसदी की वृद्धि हुई। मिडकैप कंपनियों ने मुनाफे के मोर्चे पर भी बड़ी कंपनियों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। मिडकैप कंपनियों के मुनाफे में सालाना आधार पर औसतन 1.6 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई जबकि शीर्ष पांच आईटी सेवा कंपनियों का प्रदर्शन लगभग स्थिर रहा। मुख्य तौर पर लागत में कमी के बल पर छोटी आईटी कंपनियां लॉकडाउन के प्रभाव को कम करने में सफल रहीं। जून तिमाही के दौरान पुणे की कंपनी हेक्सावेयर टेक्नोलॉजिज के राजस्व में एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 20 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।

मुंबई की कंपनी के मुख्य कार्याधिकारी आर श्रीकृष्ण के अनुसार, तिमाही के दौरान फ्रेशरों और बाहरी नियुक्तियों (अनुभवी लोगों की) पर रोक लगा दी गई और प्रदर्शन के आधार पर कुछ लोगों को बाहर किए जाने से कंपनी को अपनी लागत घटाने में मदद मिली। कंपनी के कर्मचारियों की संख्या में क्रमिक आधार पर करीब 1,200 की कमी आई। माइंडट्री का कुल खर्च भी सालाना आधार पर करीब 4.2 फीसदी घटकर 1,659.2 करोड़ रुरुपये रहा गया जिसे उपठेकेदारी और यात्रा लागत में कमी से बल मिला।

परसिस्टेंट सिस्टम्स के राजस्व में सालाना आधार पर 17 फीसदी और मुनाफे में 9 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। क्लाउड माइग्रेशन और मोबिलिटी सॉल्यूशंस जैसे क्षेत्रों में मांग बढ़ने से कंपनी के प्रदर्शन को बल मिला। विशेषज्ञों ने कहा कि आगामी तिमाहियों में मझोली आईटी कंपनियों के प्रदर्शन में सुधार जारी रहेगा जिसे कंपनियों द्वारा हासिल बड़े सौदों से उसे बल मिलेगा।